आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 23.09.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5 हजार 310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सीएजी रिपोर्ट ने की पुष्टि।
- देहरादून में अवैध अतिक्रमण को लेकर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी।
- अल्मोड़ा में वोकल फॉर लोकल के तहत महिलाओं की आर्थिकी हो रही मजबूत।
- नैनीताल जिले के सुनकिया गांव में शुरू हुआ ग्रामीण महिलाओं का सामुदायिक होम स्टे–घस्यारी।

कैग रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक– सी.ए.जी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5 हजार 310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सी.ए.जी की रिपोर्ट में दर्ज यह उपलब्धि उत्तराखंड की सुशासन की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प से प्रेरणा लेकर राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्ध भविष्य की दिशा में रखा गया एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन की नीति पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

अवैध अतिक्रमण

देहरादून में अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से व्यवसायिक या आवासीय निमार्ण को किसी स्तर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण, अवैध कार्यों को रोकने के लिए तेजी से अभियान चला रहा है और लोगों को वैध प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि लोगों को यह संदेश मिल सके कि अवैध काम के बजाय ''ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम'' के ज़रिए नक्शे स्वीकृत करवाएँ।

जीएसटी

वस्तु और सेवा कर – जीएसटी सुधारों के बाद लोग अब इन बदलावों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना कल से लागू हुई, जिसके अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो टैक्स स्लैब में बदलकर सरल बना दिया है।ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करेंगे।

महिला हाट

अल्मोड़ा के गांधी पार्क चौघानपाटा में स्थित स्वयं सहायता समूह ''महिला हाट'', स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही हस्त शिल्प, एपण आदि कार्य से महिलाओं को जोड़कर उनकी आर्थिकी का आधार बन रहा है। ''महिला हाट'' का स्थानीय उत्पादों को देश–विदेश तक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों में लगने वाले व्यवसायिक मेलों में स्वयं सहायता समूह महिला हाट द्वारा व्यावसायिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। महिला हाट के व्यवसायिक प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि महिला हाट स्वयं सहायता समूह से स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों से 120 महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं हस्त निर्मित उत्पाद बनाकर और स्थानीय उत्पादों का संग्रहण कर यहां लाती हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक मेलों में भी महिला हाट द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती हैं।

समूह की सदस्य प्रेमा ने बताया कि वे हाथ से बनी स्वेटर, विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाले एपन, मसाले, स्थानीय उत्पाद यहां पर लाते हैं, जिनसे उनको आर्थिक लाभ होता है।

घस्यारी होम स्टे

सतत पर्यटन की दिशा में अहम पहल करते हुए नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के समीपवर्ती गांव सुनकिया की ग्रामीण महिलाओं ने 'घस्यारी' नाम से सामुदायिक होम स्टे की शुरुआत की है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को पारंपरिक कृषि आधारित आजीविका से आगे बढ़कर अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध कराएगी। घास काटने के कार्य से पहचानी जाने वाली 'घस्यारी' कही जाने वाली ग्रामीण महिलाओं ने अब अपने घरों का एक–एक कमरा अतिथियों के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे मेहमानों को वास्तविक ग्रामीण जीवन का अनुभव मिल सके। इस परियोजना की तैयारी के लिए महिलाओं को 'उद्यम सहेली' कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायिक मार्गदर्शन और सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे उन्होंने पारंपरिक पत्थर और लकड़ी का उपयोग कर अपने घरों का नवीनीकरण किया और कुमाउनी वास्तुकला की झलक बरकरार रखी। 'यह समुदाय आधारित मॉडल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा और इसे उत्तराखंड के अन्य गाँवों में भी दोहराया जा सकेगा। 'घस्यारी' केवल ठहरने की सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदार ग्रामीण पर्यटन की नई राह और महिलाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बनेगी और पर्यटकों को कुमाऊं की संस्कृति से सीधे जोड़ने का अवसर देगी।

ट्रायल

नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आगामी 8 और 9 अक्टूबर को ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के लिए कुल 17 खेल स्पर्धाओं में जनपदीय चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी वरूण बेलवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, कैरम, शतरंज, हाकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, भारोत्तोलन, वेस्ट फिजिक्स, तैराकी, वालीबाल, टेबल–टेनिस, कुश्ती, खो–खो, क्रिकेट और फुटबाल में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को आधार कार्ड और सम्बंधित विभागाध्यक्ष का अनुमति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।